राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

ई–मेल–pr.rajbhavan@gmail.com
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल–9431283596

प्रेस–विज्ञप्ति

राजभवन में वित्तीय परामर्शियों एवं वित्त पदाधिकारियों की समीक्षा–बैठक आयोजित हुई

पटना, 24 अक्टूबर 2018

महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन के निदेशानुरूप आज राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के वित्तीय परामर्शियों तथा वित्त पदाधिकारियों की एक समीक्षा–बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वित्त अधिकारियों एवं वित्तीय परामर्शियों को यह निदेशित किया गया है कि पिछले महीने जिन महाविद्यालयों में कुलपतियों, प्रतिकुलपतियों, कुलसचिवों एवं महाविद्यालय निरीक्षकों के निरीक्षण के दौरान वित्तीय अनियमितता की जो शिकायतें और कमियाँ मिली थीं, उनका त्वरित निराकरण कराना वे सुनिश्चित करें तथा दोषी पदाधिकारियों या कर्मियों को चिह्नित कर अपना प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करें, ताकि आवश्यक कार्रवाई हो सके। राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री टंडन ने प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह को अपने दायित्वों का सही ढंग से निष्पादन नहीं कर पा रहे वित्त अधिकारियों या वित्तीय परामर्शियों को पदमुक्त करने का आदेश दिया है। बैठक में समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने बताया कि महाविद्यालयों में वित्तीय अनियमितता की शिकायतों की जाँच में लापरवाही बरतनेवाले वित्त अधिकारियों या वित्तीय परामर्शियों की सेवाएँ समाप्त कर दी जाएँगी।

ज्ञातव्य है कि पिछले माह हुए महाविद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि कई कॉलेजों के कैशबुक अद्यतन रूप में ठीक तरह से संधारित नहीं हैं। फलतः सभी वित्त अधिकारियों को यह निदेशित किया गया है कि महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं बर्सरों की बैठकें विश्वविद्यालय स्तर पर नियमित रूप से करते हुए वे लेखा का अद्यतन संधारण सुनिश्चित करायें, ताकि वित्तीय अनुशासन हर हालत में बना रहे।

आज की समीक्षा बैठक में महामहिम राज्यपाल के सभी निदेशों से वित्त पदाधिकारियों व वित्त परामर्शियों को अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि सेवान्त लाभ के मामलों के त्वरित निष्पादन में बाधक बननेवाले अधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध भी कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जब समुचित आबंटन उपलब्ध करा दिया गया है, ऐसी स्थिति में सेवांत–लाभ के मामलों में अनावश्यक विलम्ब कत्तई नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद शेष उपार्जितावकाश के बदले मिलनेवाली नगद राशि के भुगतान में भी आनाकानी की शिकायतें मिल रही हैं, जिन्हें काफी गंभीरता से लिया गया है। प्रधान सचिव ने कहा कि महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति का यह स्पष्ट निदेश है कि 'पेंशन अदालतें' नियमित रूप से विश्वविद्यालयों में आयोजित होनी चाहिए तथा उनमें निष्पादित मामलों के बारे में तथ्यपरक प्रतिवेदन राजभवन को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

बैठक में सभी वित्त पदाधिकारियों एवं वित्तीय परामर्शियों को कहा गया है कि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में होनेवाली विभिन्न प्रकार की खरीददारियों में 'GeM' को प्राथमिकता दी जाए, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। समीक्षा के क्रम में वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना में 'GeM' का निबंधन नहीं हो पाने को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया गया और कहा गया कि 'GeM' पर खरीददारी में लापरवाही बरतने पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

आगे पृष्ठ...2 पर

बैठक में वित्त अधिकारियों एवं वित्तीय परामर्शियों को यह भी कहा गया कि राज्य सरकार यू॰जी॰सी॰ या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) द्वारा प्राप्त आबंटनों के विरूद्ध 'उपयोगिता–प्रमाण–पत्र' ससमय भेजा जाना चाहिए, ताकि आगे के आबंटन नियमित रूप से प्राप्त होते रहें। इसमें लापरवाही होने पर जिम्मेवार अधिकारी दंडित होंगे।

बैठक में कहा गया कि शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का निर्धारित समय पर नियमित वेतन–भुगतान भी हर हालत में सुनिश्चित होना चाहिए। प्रधान सचिव ने बैठक में कहा कि आबंटन उपलब्ध रहने के बावजूद, ससमय नियमित वेतन–भुगतान नहीं होने पर जिम्मेवार अधिकारी दंडित होंगे। समीक्षा के क्रम में यह बात उभरकर सामने आई कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के वेतन–सत्यापन के कार्य में तो संतोषजनक प्रगति है, परन्तु शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन–सत्यापन का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। फलतः ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ तथा प्रोन्नति आदि के मामले भी ससमय निष्पादित नहीं हो पा रहे हैं। प्रधान सचिव ने कहा कि सभी वित्त पदाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शी 'वेतन–सत्यापन' के कार्यों को प्राथमिकतापूर्वक निष्पादित करायें।

आज की बैठक में प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह, अपर सचिव श्री विजय कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी (वि॰वि॰) श्री अहमद महमूद सहित राज्यपाल सचिवालय के अन्य वरीय अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

.....